श्री मानन्द यादव : मिस्टर स्वामी जो लोक सभा के जनता पार्टी के सदस्य है उन्होंने यह कहा कि भारत सरकार की कैबीनेट में 12 मंत्री ऐसे हैं जो शराब पीते है । क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि पहले अपने मंत्रिमंडल में प्रोहिबीशन लागू करने के बाद ही हिन्दुस्तान की डिफेंस फोर्सेज के ऊपर प्रोहिबीशन सिस्टम को लागू करने की बात सोचेगी ?

MR. CHAIRMAN: This is not a supplementary arising out of this.

श्री रामानन्द यादव : पहले आप अपना सुधार करें फिर आगे जाये ।

SHRIMATI MARGARET ALVA: The Prime Minister has made a statement that over 50 per cent of the Defence Forces do not take liquor and that is why introduction of prohibition there will not be a problem. I would like to ask the Minister if figures are available of the actual percentage of Armed Forces personnel who are teetotallers and do not use alcoholic drinks at all.

DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER: I require notice for this question.

SHRI RAMANAND YADAV: Sir, my question was not answered.

MR. CHAIRMAN: It was not to be answered.

SHRI RAMANAND YADAV: Have you ordered him not to reply?

MR. CHAIRMAN: There was nothing to be replied.

Uniform policy for slum clearance

*185. SHRI SITARAM KESRI: Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under Government's consideration to formulate a uniform policy for slum clearance/improvement for being followed by all the States to minimise hardships to the slum/jhuggi-jhopri dwellers in the country;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) whether the Central Government have received any complaints regarding demolitions carried out by the Rajasthan Government rendering a large number of families homeless in that State as reported in the press on the 25th January, 1978; and

(d) if so, what action the Central Government have taken or propose to take in the matter?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम किंकर) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा है ।

विवरण

(क) तथा (ख) गन्दी बस्ती उन्मूलन सुधार योजना 1956 में केन्द्रीय क्षेत्र में आरम्भ की गई थी तथा 31 मार्च, 1969 तक इसी रूप में जारी रही । 1-4-1969 से यह योजना राज्य क्षेत्र में हस्तान्तरित कर दी गई है तथा इसकी वित्त व्यवस्था राज्यों द्वारा केन्द्रीय सरकार से राज्य प्लान योजनाओं के लिए प्राप्त समेकित ऋणों तथा समेकित अनुदानों में से की जाती है । इस योजना की मूलभूत विशेषता गन्दी बस्तियों के निवासियों को मौजूदा स्थलों या उनके आस-पास के क्षेत्र में ही पुनः बसाना है तथा पर्यावरणीय स्वास्थ्य के न्यूनतम मानकों की व्यवस्था करना है । इस योजना के निम्नलिखित तीन मूलभूत अंग हैं :—

(1) गन्दी बस्तियों में रह रहे पात्र परिवारों को विकसित प्लाट, साधारण मकान, शयनशाला होस्टल की तरह के वास तथा पक्के टेनामेन्ट देकर पुनः बसाना ।

(2) जिन शहरों तथा कस्बों में पटरी पर रहने वालों की अत्याधिक समस्या है, वहां रैन बसेरे बनाना ।

(3) गन्दी बस्तियों की पर्यावरणीय दशा में सुधार तथा गन्दी बस्तियों के पक्के मकानों में सुधार ।

इस योजना की ये मूलभूत विशषताएं मुख्यतया सभी राज्यों में लागू हैं । तथापि, इस योजना के पृथक-पृथक ब्यौरे स्थानीय दशा के अनुसार अलग-अलग होते है । इस संबंध में एक समान नीति बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नही है ।

(ग) निर्माण और आवास मंत्रालय में ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

†[THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI RAM KINKAR): (a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) The Slum Clearance/Improvement Scheme was started in 1956 in the Central sector and continued as such upto 31st March, 1969. With effect from 1-4-69, the Scheme stands transferred to the State sector, to be financed by the States out of block loan and block grant given by the Central Government for State Plan schemes. The basic feature of the scheme was to rehouse the slum dwellers at the existing sites or nearby and to provide minimum standards of environmental hygiene. The scheme has the following three basic components:—

(1) Rehousing eligible families living in slum areas through provision of developed plots, skeletal houses, dormitory|hostel type of accommodation and pucca tenements.

(2) Construction of night-shelters in cities and towns with acute problem of pavement dwellers.

(3) Improvement of environmental conditions in slum areas and improvement of pucca built dwellings in slum areas.

These basic features of the scheme are broadly applicable in all the States. However, the individual details of the scheme are flexible depending on local conditions. No proposal to formulate any uniform policy in the respect is under consideration of the Government.

(c) No such complaint has been received in the Ministry of Works and Housing.

(d) Does not arise.]

श्री सीताराम केसरी : सभापति जी, क्या मंत्री महोदय को इस बात की सूचना है कि जयपुर नगर में जहां पर कि जो बस्तियां गन्दी नही थी, अब पक्के मकानों मे लोग बसे हुए थे, वहां पर तकरीबन 200 लोगों को डिमालिश करके हटा दिया गया ? इसमें यह कहा गया कि यह इमरजेंसी का ही एक दूसरा रूप है और उसी के अनुसार यह चीज चल रही है । इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आपको इसकी सूचना है और अगर है तो आपने क्या एक्शन लिया ?

श्री राम किंकर : मान्यवर, मैंने उसका जवाब दे दिया है । आप 'ग' देखें, प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री सीताराम केसरी : आपने लिखा है कि प्रांत की सरकार के जिम्मे कर दिया गया है । यदि प्रांत की सरकार के जिम्मे कर दिया गया है और उनके अन्तर्गत इस तरह की ज्यादतियां हो रही है तो क्या आपने इस दिशा में कोई ऐक्शन लिया है अथवा क्या उनको कोई निर्देश दिया है ?

श्री राम किंकर : मान्यवर, मेरे पास इस तरह की कोई इत्तिला नही है कि राजस्थान में या जयपुर में किसी स्थान पर मकान गिराये गये हैं ।

†[ ] English translation.

श्री सीताराम केसरी : क्या सरकार को इस बात की सूचना है कि ग्रेटर कैलाश में बहुत से मकान धराशायी किये गये है और उनके पुनर्वास का अभी तक कोई प्रबंध नहीं हुआ है ।

श्री राम किंकर : मान्यवर, इससे यह प्रश्न नहीं उठता है ।

SHRI S. K. VAISHAMPAYEN: According to the statement given by the Minister, the scheme for slum clearance has been transferred to the State sector and the Centre only gives financial assistance. May I know from the honourable Minister whether this particular financial assistance is earmarked for the States to be spent only on slum clearance, and if so, what methods the Government has or what procedures the Government has, to see and check that these sums are spent only on slum clearance?

SHRI SIKANDAR BAKHT: This scheme was transferred to the States on the 1st April, 1969, and no direct financial assistance is being provided for undertaking projects of slum clearance. With the transfer of the scheme to the State sector the State Governments are free to use the block assistance in the shape of loan|grant being given to them.

SHRI S. K. VAISHAMPAYEN: My question was whether this particular financial assistance is earmarked for the State Governments to be spent on slum clearance only.

SHRI SIKANDAR BAKHT: My answer is that the loans and grants are given in a block form and the State Government are within their right to use them in the manner they like.

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : श्रीमन्, मंत्री जी ने कहा है कि उनको राजस्थान या जयपुर में उजाड़ी गई बस्तियों के बारे में कोई जानकारी नहीं है । मैं इस संबंध में दो सवाल पूछना चाहती हूं । क्या यह सही नहीं है कि जब वहां इस तरह की बस्तियों को उजाड़ा गया था तो वहां पर एक जबर्दस्त डिमांस्ट्रेशन हुआ था, एक जलूस निकला था । दूसरा सवाल यह है कि जब यह सवाल एडमिट किया गया तो आपने जयपुर से यह क्यों नही दरियाफ्त करवाया कि वहां पर ऐसी कोई घटना हुई या नही ?

श्री राम किंकर : मान्यवर, मेरे पास इस तरह की कोई सूचना नहीं आयी ।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : यह क्या सवाल हुआ कि जबर्दस्ती क्यों पूछू । मैंने आपसे यह सवाल पूछा था कि आपको दरियाफ्त करके जवाब देना चाहिए था वरना आपको यह सवाल ही नहीं एडमिट करना चाहिए था ।

श्री राम किंकर : प्रश्न यह पूछा गया था कि क्या केन्द्रीय सरकार को राजस्थान सरकार द्वारा आवासों को गिराये जाने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है ?

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : यह आपको पूछ कर जवाब देना चाहिए था । वहां पर हजारों आदमी बेघरबार हो गये हैं।

(Interruptions)

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी : इस पर आपका संरक्षण होना चाहिए, मान्यवर, यह गैर जिम्मेदाराना जवाब है ।

श्री सिकन्दर बख्त : अगर हमारी माननीय सदस्या को बहुत इच्छा है तो हम पूछ लेंगे ।

PROF. D. P. CHATTOPADHYAYA: May I know from the hon. Minister whether he is aware that the block grant given to the States is a sort of lump grant, unspecified and not project linked? He must also be aware that in many States this money is not available at all for the implementation of the policy. Therefore, will the Government be kind enough to consider a

proposal which was mooted three of four years back in the All India Conference of Local Self Governments that there should be a Municipal Finance Commission along the lines of Finance Commissions so that the financial position of these city administrations or town administrations is somewhat solvent so that this sort of constructive programmes, which are very useful, does not remain only on paper, but could be implemented? This block assistance, I am sure that the hon. Minister is aware, is now more on paper than of any real help. Secondly, in view of the awful paucity of funds, some of the cities are taking grants and assistance from international financial institutions and organisations. Since we have been talking about a uniform policy. what is the attitude of the Government of India to the State Governments—since it is a State subject—on their own seeking assistance from the World Bank or other organisations to finance these projects?

SHRI SIKANDAR BAKHT: Since they are primarily only suggestions and not questions seeking information, they will be noted. Since the hon. Member has made the suggestion, it is being taken note of.

PROF. D. P. CHATTOPADHYAYA: There was a resolution adopted about having a Municipal Finance Commission. Secondly, the CMP in Calcutta is taking grants from the World Bank. Since a uniform policy is being talked about, I would like to know whether the same is true of Bombay or other State Governments.

SHRI SIKANDAR BAKHT: In the reply it has been said that no proposal . . .

SHRI KHURSHED ALAM KHAN: It is for you to decide whether it is a question or suggestion.

SHRI SIKANDAR BAKHT: . . . to formulate any uniform policy in this respect is under the consideration of the Government.

SHRI U. R. KRISHNAN: I would like to know from the hon. Minister whether the Government will give subsidy to the State Governments which are implementing the slum clearance programme. From the answer given by the hon. Minister I understand that there are so many night-shelters in cities and towns. May I know which are the States having these night-shelters in cities and towns?

SHRI SIKANDAR BAKHT: The position is that a Committee was appointed by the Ministry on the recommendations of the Housing Minister Conference held in Madras in June, 1974, to review the slum clearance improvement scheme. These recommendations were submitted to the Ministry in 1975, but unfortunately the Planning Commission is taking an adverse view on these recommendations. We are considering all those recommendations very actively to see if it is possible to give them some sort of help.

SHRI U. R. KRISHNAN: Sir, my question has not been answered. The question was whether for implementing the slum clearance . . .

SHRI SIKANDAR BAKHT: That has been answered.

MR. CHAIRMAN: You want to put a question?

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी : सभापति महोदय, एक स्पष्टीकरण चाहती हूं ।

MR. CHAIRMAN: No *spashtikaran.* He is on his legs. You may ask a supplementary.

SHRI CHARANJIT CHANANA: The hon. Minister must be knowing that it is not a suggestion but in August, 1976 after the Vancouver Conference organised by the United Nations, some habitat funds were created and the Philippines is one country which is drawing on this fund which is used for resettlement of slum dwellers. I would like the hon. Minister to tell the House whether his Government has done something in

that direction. Our Government had tried in the United Nations for getting part of that fund.

SHRI SIKANDAR BAKHT: I will require notice to answer this question.

*136. [*The questioner (Shri Janardhana Reddy) was absent for answer* vide *Col.* 38 infra.]

Decline in the Standard of Sports in the Country

*187. SHRIMATI HAMIDA HABIBULLAH:
SHRI SAWAISINGH SISODIA:
SHRI SAT PAUL MITTAL:

Will the Mnister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the standard of sports in the country has gone down;

(b) if so, what are the reasons therefor; and

(c) what steps Government are taking to improve the standard?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धन्ना सिंह गुलशन) : (क) जी, नहीं । सामान्य रूप से यह कह देना बिल्कुल सही नहीं होगा कि देश में खेलों का स्तर गिर गया है ।

(ख) प्रश्न नही उठता ।

(ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

खेलों के स्तरों में सुधार के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(i) राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं और प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन के लिए राष्ट्रीय खेल संघों/परिषदों को वित्तीय सहायता देना, वेतन भोगी सहायक सचिवों को वेतन की अदायगी, खेल उपस्कर की खरीद और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भाग लेना ;

(ii) उच्च कोटि के प्रशिक्षकों को तैयार करने हेतु पटियाला में राष्ट्रीय खेल संस्थान तथा बंगलौर में इसकी शाखा की स्थापना ;

(iii) राज्य स्तर पर प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन, स्टेडियमों, तरण तालों के निर्माण, खेल के मैदानों, अंतरंग स्टेडियमों के विकास, मैदानों में तेज रोशनी करने के लिए राज्य खेल परिषदों की आर्थिक सहायता;

(iv) ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में खेलों को व्यापक आधार देने के उद्देश्य से खण्ड स्तर से लेकर ऊपर की ग्रामीण खेल प्रतियोगिताओं को आयोजित करना ;

(v) राज्य और इससे कम स्तरों पर प्रतियोगिताएं करने के बाद महिलाओं के लिए प्रतिवर्ष एक राष्ट्रीय खेल समारोह आयोजित करना ;

(vi) विशिष्टता के उच्च स्तरों को प्राप्त करने की योग्यता दिखाने वाले स्कूली लड़कों और लड़कियों को प्रति वर्ष 1200 खेल प्रतिभा खोज छात्रवृत्तियां प्रदान करना ;

(vii) प्रति वर्ष उत्कृष्ट पुरूष व महिला खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार प्रदान करना ;

(viii) खेलों के लिए भौतिक सुविधाओं के सृजन हेतु विश्वविद्यालयों और कालेजों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से और अन्तर विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिताओं तथा

†The question was actually asked on the floor of the House by Shrimati Hamida Habibullah